International Journal of Applied Research 2021; 7(2): 375-380

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(2): 375-380
www.allresearchjournal.com
Received: 26-11-2020
Accepted: 15-01-2021

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
शोधार्थी, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. महानंद द्विवेदी
प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊगंज, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
शोधार्थी, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

रीवा जिले के जवा विकासखण्ड में परिवर्तनशील ग्रामीण समाज में राजनीति और अपराधीकरण : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं डॉ. महानंद द्विवेदी

सारांश
इस शोध पत्र के द्वारा रीवा जिले के जवा विकासखण्ड में परिवर्तनशील ग्रामीण समाज में राजनीति और अपराधीकरणः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। अध्ययन के दौरान देखा गया कि शोध क्षेत्र में 12 प्रतिशत बुद्धिजीवी वर्ग, 11 प्रतिशत नौकरी पेशा वर्ग, 12.5 प्रतिशत व्यापारी वर्ग, 21 प्रतिशत जनप्रतिनिधि व समाज के अन्य वर्ग के अभिमतानुसार समाज के अनेक वर्गों के लोगों से अनेक अपराधों में राजनीतिक संलिप्तता देखने को प्राप्त होती है। समाज के अनेक वर्गों के लोगों से पुलिस पर राजनीतिक दबाब को देखकर लोगों के मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि पुलिस अपराधियों से मिली रहती है के पक्ष में 12 प्रतिशत बुद्धिजीवी वर्ग, 11 प्रतिशत नौकरी पेशा वर्ग, 12.5 प्रतिशत व्यापारी वर्ग, 22 प्रतिशत जनप्रतिनिधि व समाज के अन्य वर्ग के अभिमत प्राप्त हुए है। शोध क्षेत्र में 11 प्रतिशत बुद्धिजीवी वर्ग, 12 प्रतिशत नौकरी पेशा वर्ग, 14 प्रतिशत व्यापारी वर्ग, 22 प्रतिशत जनप्रतिनिधि व समाज के अन्य वर्ग के अभिमतानुसार अपराध नियंत्रण में एक मुख्य समस्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होना है।

मुख्य शब्द – रीवा जिला, जवा विकासखण्ड, ग्रामीण समाज, राजनीति, अपराधीकरण, समाजशास्त्रीय

प्रस्तावना
भारत देश एक प्रजातांत्रिक देश है, जिसका संचालन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। देश में सत्ता लोलुपता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति व अनेक राष्ट्रीय नेताओं के दिशाहीन स्वार्थों व संकीर्ण नेतृत्व के कारण राष्ट्रीय जीवन भ्रष्ट और अनुशासनहीन हो गया है, देश की दल बदल राजनीति ने लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर दिया है। जाति भाषा व धर्म के आधार पर राजनीति लोकतंत्रीकरण के लिये घातक सिद्धि हो सकती है। प्रो. योगेन्द्र सिंह के अनुसार भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक उल्लेखनीय पक्ष भारतीय राजनीति में जाति की घुसपैठ है। प्रो. कोठारी के अनुसार जिसे राजनीति का जातिवाद कहा जाता है वह वास्तव में जाति का राजनीतकरण है। [1]

आज ऐसे राजनीतिक दलों और विघटनकारी तत्वों की कमी नहीं है, जो अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिये तथा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिये किसी भी चाल चलने के पीछे नहीं होते हैं। इनमें से कुछ के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं और कुछ के अभी भी शेष है।

ऐसे सफेद पोश अपराधी किस प्रान्त में और कितने हैं यह स्पष्ट नहीं है परन्तु यह सुनिश्चित है कि प्रत्येक जिले में 8–10 अपराधी और 1–2 उनके सरगना रहते हैं जो लाठी की ताकत एवं राजनीतिकों का सहारा लेकर प्रशासन की दहलीज पार करके प्रान्तीय विधान तथा तदुपरान्त शासन के मंत्रिमण्डल तक पहुंच जाते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश का शासन हमारे हाथ में आया तब हमें ब्रिटिश शासनकाल की पुलिस मिली जिसका स्वरूप एक दिन में नहीं बदला जा सकता, उसकी भावना, संगठन, प्रशिक्षण और दृष्टिकोण भी वही बना रहे जो अंग्रेजी शासनकाल के समय थी। पुलिस की जनसेवा की भावना पर ध्यान नहीं दिया गया और पुलिस अधिकतर शासन के रूप में कार्य करती रही, जनता ने पुलिस के कार्य एवं व्यवहार से कोई अन्तर महसूस नहीं किया।

लोगों का विचार किसी भी विभाग के बारे में उसके कर्मचारियों, सदस्यों के व्यक्तिगत कार्य और कार्य करने के तरीके पर ही निर्भर करते हैं। पुलिस विभाग का कोई कर्मचारी अगर अभद्र व्यवहार करे तो उसका असर पूरे विभाग पर पड़ता है और वह विभाग जनता की नजरों से गिर जाता है। इस बात पर किसी को संदेह नहीं है कि पुलिस विभाग में बहुत से कर्मचारी, अधिकारी अच्छा कार्य करते हैं, कर्तव्य पालन करने के सदा इच्छुक रहते हैं फिर भी कहीं न कहीं विभाग का कोई कर्मचारी ऐसा कार्य कर देता है जो बदनामी का कारण बन जाता है और पुलिस जनता का

सहयोग प्राप्त नहीं कर पाती है। [2]

पुलिस के आपसी मतभेद, ब्रिटिश कालीन छवि, स्थानीय व निम्न कर्मचारियों के कारण एवं फिल्मों व नाटकों में अत्यधिक निम्न स्तर का स्वरूप प्रदर्शित करने के कारण आज भी जनता में पुलिस के प्रति अविश्वास की भावना जागृत है, जिस कारण से अपराधों के सम्बन्ध में वास्तविक जानकारी पूर्णरूपेण पुलिस को प्राप्त नहीं हो पाती है।

पुलिस, जनता एवं शासक की आदिकाल के ऐतिहासिक स्रोतों के अध्ययन से स्पष्ट है कि मात्र यही अपेक्षा थी कि समाज में किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था कायम रहे यही जन सामान्य की अवधारणाएँ रही हैं। परन्तु इन्हीं कार्यों के साथ सल्नत काल, मुगल काल व ब्रिटिश काल में राजनैतिक विरोधियों के आंदोलनों को एवं आंदोलनकारियों को दबाने के लिए एवं शासन को क्षति न हो इस उद्देश्य से पुलिस के कार्य में कुछ परिवर्तन शासन तन्त्र द्वारा लाये गये जो तत्कालीन सत्ता पक्ष के हित में थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता पश्चात एक गणतंत्रात्मक राज्य में पुलिस से अनेक प्रकार की अपेक्षायें की जाती है। [3] ब्रिटिशकालीन पुलिस की छवि आम भारतीयजनों के मन में जो पूर्णरूप से है उसे इतनी सरलता से कम किया जाना असंभव है। साथ ही आज भी जो पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के मन में आम आदमी से व्यवहार की रूढ़ि बनी है उसे भी सरलता से बदलना संभव नहीं हैं, पुलिस अधिकारियों में जनता से सहयोग और विनम्रता का व्यवहार करने के लिये हमें पुलिस अधिकारियों की मानसिकता को पूर्ण रूप से बदलना पड़ेगा। पुलिस कार्यों में सफलता के लिये पुलिस और जनता में मधुर सम्बन्ध, विश्वास व लोकप्रियता उत्पन्न करना जरूरी है। पुलिस और जनता के सम्बन्ध में पं. जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि पुलिस और जनता के सम्बन्ध जितने मधुर होंगे पुलिस का कार्य उतना ही सफल होगा। [4]

पुलिस का कार्य लगभग सूचना तंत्र पर आधारित है, जिसकी अपेक्षा जनता से की जाती है यह बात सत्य है कि सदियों से पुलिस पर लगे आक्षेपों को जन सामान्य के मन से अतिशीघ्र निकालना सहज कार्य नहीं है परन्तु इन दोनों के मध्य किसी उपाय की खोज की जाना आवश्यक है जिससे दोनों की अपेक्षाओं की एकरूपता लाई जा सके और पुलिस को जनता का एवं जनता को पुलिस का सहयोग प्राप्त हो सके।

आर. हैल्डन ने पुलिस की छवि के बारे में कहा है कि पुलिस की छवि के प्रति अवधारणा की स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसमें एक निश्चित उद्देश्य का अभाव है। जन सामान्य द्वारा पुलिस के सम्बन्ध में विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न–भिन्न विचार प्रकट किये जाते हैं तथा इन विचारों की स्थिति में परिवर्तन भी होते रहते हैं। पुलिस के सभी कार्य जनता से जुड़े होते हैं और जनता के मध्य ही सभी कार्यों का निर्वहन भी करना पड़ता है जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है, दुर्भाग्यवश पुलिस द्वारा जो भी कार्य व्यवहार किये जाते हैं उसके बारे में आम जनता की राय अच्छी नहीं है।

जन सामान्य का व्यक्ति यदि पुलिस विभाग में नौकरी कर लिया है तो लोगों को उसके प्रति जो उन्हीं के बीच में रहता था धारणाएँ बदल जाती है। [5]

पुलिस सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है इसलिये जनता के प्रतिनिधियों को पुलिस अधिकारियों से अधिक सम्पर्क करना पड़ता है।

पुलिस तथा जनप्रतिनिधियों के आपसी महत्व का ध्यान रखते हुए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा इन विषय पर विशेष निर्देश जारी किये गये हैं एवं समय–समय पर निर्देश जारी किये जाते है। [6]

मीडिया का अर्थ माध्यम होता है The Media of communication are television radio and the press जिससे स्वयं स्पष्ट होता है कि पुलिस का दूरदर्शन, रेडियो और प्रेस के माध्यम के सम्बन्ध से है। यह सम्पूर्ण संचार माध्यम वर्तमान समय में बहुत ही सरल व अत्यन्त सुलभ कीमतों में उपलब्ध रहती है यहां तक की यह सम्पूर्ण संचार माध्यम, सामान्य परिवारों के दैनिक उपयोग में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के रूप में उपलब्ध रहती है जो समस्त क्षेत्रों में उपयोग में लायी जाती है। [7]

पुलिस का जनमानस में सामंजस्य पूर्ण सौहार्द्र स्थापित करने में पत्रकारों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती हैं, पत्रकारों (मीडिया) के माध्यम से व्यक्त किये गये विचार जनमानस की भावनाओं में मोड़ लाने के लिए जनता पर गहरा प्रभाव डालते हैं और प्रेस की सभी बातों को जनता निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लेती है, वर्तमान में समाचार पत्र, समाज, देश व प्रजातंत्र के अनिवार्य अंग बन चुके हैं। [8]

देश के अन्य भागों की भांति विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों का वितरण अध्ययन क्षेत्र में भी होते हैं इनमें दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र, पाक्षिक समाचार पत्र व स्थानीय समाचार पत्र होते हैं जिनके पत्रकार शहर व कस्बा आदि में घूम फिर कर समाचार एकत्र करते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से जब भी कोई जानकारी मीडिया के लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो भी जानकारी उपलब्ध हो या जानकारी न हो तो उस सम्बन्ध में उन्हें नम्रतापूर्वक जानकारी देना चाहिए और साथ ही किसी जानकारी को प्रकाशित करने पर यदि किसी अन्य अपराधों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो इसे न प्रकाशित करें यह भी अवगत कराया जाना चाहिए। [9]

प्रेस की स्वतंत्रता प्रजातंत्र की नींव है। प्रेस व पत्रकारों द्वारा पुलिस की वास्तविक आलोचना की जावे और पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह अपने प्रतिकूल आलोचना से बचे। पत्रकारों द्वारा पुलिस व न्याय व्यवस्था को मार्गदर्शन दिया जा सकता है, परन्तु पुलिस द्वारा की जाने वाली अच्छाइयों का भी प्रकाशन प्रेस द्वारा उसी तत्परता से की जानी चाहिए। पुलिस व प्रेस के मध्य किसी भी प्रकार विवाद किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है बल्कि एक दूसरे से हाथ मिलाकर साथ–साथ चलकर समाज का हित करना चाहिए। [10]

सामाजिक विधानों द्वारा नारी की सुरक्षा और सम्मान का दायित्व अपने ऊपर लेकर सुरक्षा संगठन ने पुलिस को सौंप दिया और सामाजिक सुरक्षा के साथ ही साथ पुलिस का कार्य नारी सुरक्षा भी है।

हमारे देश में विधि द्वारा महिलाओं और बालकों को विधिक सुरक्षा जिससे उनकी लज्जा या मर्यादा न भंग हो और बालक के कोमल मन पर कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया न हो संरक्षण दिया गया है, जिसके अनुरूप पुलिस अधिकारियों को उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों व महिलाओं से प्रत्येक क्षेत्र में सौजन्यपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

पुलिस के सम्पर्क में महिलाएँ व बच्चे रिपोर्टकर्ता, गवाह के रूप में या कभी–कभी किन्हीं सामाजिक परिस्थितियों के कारण अपराधी के रूप में भी सम्पर्क में आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त दस्यु अपराधी के परिवार, रिश्तेदार के रूप में भी महिलाओं व बच्चों से पुलिस के सम्पर्क हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी पुलिस को बच्चों व महिलाओं से सौजन्यपूर्ण व शालीनता से व्यवहार करना चाहिए क्योंकि यदि महिलाओं और बच्चों के परिवार के लोग अपराधी भी है तो उनसे क्रूरता से पुलिस को कोई लाभ नहीं प्राप्त होना हैं। बल्कि शालीनता व सहजता से बातें करने पर अपराधी को अपराध छोड़ने की भी कुछ आशाएँ प्राप्त की जा सकती है और महिलाओं व बच्चों के साथ क्रूरता आदि करने पर अपराधी को अपराध की ओर बढ़ावा के लिये अग्रसर करने में सहायक हो सकती है।

संस्कृत मे मनु ने कहा था कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात् जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है, अतः पुलिस द्वारा नारी के साथ शालीनता का व्यवहार किये जाने पर पुलिस के लिए हितकारी होगा। [11]

युवा वर्ग किसी भी राष्ट्र के उत्थान का एक सशक्त माध्यम होता है। युवा शक्ति केवल भारत में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के रचनात्मक कार्यों से राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन में बृहद योगदान दे चुके हैं।

युवा वर्ग के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं, अपने देश के लगभग 75 प्रतिशत युवा वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, जो संगठित नहीं है।

अभी तक भारत के विशाल युवा वर्ग का कोई वैज्ञानिक या सामाजिक अध्ययन नहीं किया गया जिससे कि पुलिस को इनसे किसी समस्याओं पर विशिष्ट योगदान प्राप्त हो सके।

यह सत्य है कि आज के युवा वर्ग में स्वयं की पहचान का प्रश्न अहं है परन्तु उसका कारण बेरोजगारी, स्वार्थपरक, राजनैतिककरण, दिशाविहीन शिक्षा, सामाजिक मूल्यों एवं मान्यताओं के प्रति अनास्था, सामाजिक व राजनीतिक असमानताएँ जिसमें आज की दिशाविहीन शिक्षानीति प्रमुख है।

आज के परिवेश में परिवार स्कूल, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में भारतीय परम्परा के अनुकूल पिता, पुत्र, गुरू शिष्य की परम्परा के प्रतिकूल वातावरण बनता जाता है। आज गुरू और शिष्य के बीच कोई भाषात्मक सम्पर्क नहीं है, ये विद्या के केंद्र न होकर अपनी सापेक्षता खो रहे हैं, रचनात्मक कार्य के अभाव में शिक्षा की दिशा, छात्रों व युवा वर्ग को भ्रमित कर रही है। [12] परन्तु इसके लिये मात्र युवा वर्ग दोषी नहीं है बल्कि समाज के वे प्रबुद्ध नागरिक व सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता एवं उच्च शिखर पर बैठे राजनेता और अधिकारी वर्ग जिसका इस ओर ध्यान आकृष्ट नहीं हो पा रहा है, न इन राष्ट्र के धरोहरों को अच्छी दिशा दे पा रहे हैं जो देश के भविष्य को निश्चित ही अन्धकार के मार्ग की ओर ले जा रहा है।

यदि सामाजिक, राजनैतिक, बुद्धिजीवी वर्ग एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, साथ थाना स्तर पर थाना प्रभारी अपने क्षेत्रों के नवयुवकों का ध्यान किसी समस्या की ओर आकृष्ट कर सकें तो निश्चित ही सफलता पुलिस की झोली में होगी।

नवयुवकों को अपनी ओर आकृष्ट करना बहुत कठिन कार्य नहीं है और इससे पुलिस के साथ–साथ समाज को भी अत्याधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। [13]

पिछले कुछ समय में राजनीतिक व्यक्तियों से अपराधियों के सम्बन्ध की बातें सुनने व देखने को प्राप्त होती है। कहीं–कहीं राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण कतिपय पुलिस अधिकारियों द्वारा अनिच्छापूर्वक राजनैतिक दबाबवश कुछ कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के इच्छानुरूप ही पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानान्तर भी होते हैं। जिससे पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का मनोबल हतोत्साहित होता है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि पुलिस जनप्रतिनिधियों की चाटुकारिता में लग जावे बल्कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके द्वारा बताये जाने वाला कार्य यदि विधि अनुरूप हो तो करना चाहिए अन्यथा विनम्रता व शिष्टाचारपूर्वक कारण स्पष्ट करते हुये असमर्थता प्रकट करने के पश्चात भी जन प्रतिनिधि को अपने व्यवहार से संतुष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए। [14]

शोध समस्या का सीमांकन

भौगोलिक परिसीमन

प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र रीवा जिला के जवा विकासखण्ड को सम्मिलित किया गया है।

विषयवस्तु का परिसीमन

अध्ययन की विषयवस्तु का परिसीमन रीवा जिले के जवा विकासखण्ड में परिवर्तनशील ग्रामीण समाज में राजनीति और अपराधीकरणः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

शोध विधियाँ

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित विधियों एवं उपकरणों का उपयोग किया गया है –

साक्षात्कार विधि

शोध क्षेत्र में परिवर्तनशील ग्रामीण समाज में राजनीति और अपराधीकरणः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए इस क्षेत्र में बुद्धिजीवी वर्ग, नौकरी पेशा वर्ग, व्यापारी वर्ग और जनप्रतिनिधि व समाज के अन्य वर्ग से वस्तुस्थिति का पता लगाने हेतु साक्षात्कार किया गया है।

न्यादर्श चयन

रीवा जिले के जवा विकासखण्ड में परिवर्तनशील ग्रामीण समाज में राजनीति और अपराधीकरणः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए न्यादर्श के रूप में चयनित बुद्धिजीवी वर्ग 40, नौकरी पेशा वर्ग 40, व्यापारी वर्ग 40 और जनप्रतिनिधि व समाज के अन्य वर्ग 80 उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति से साक्षात्कार हेतु किया गया है।

परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

राजनीतिक व अपराधीकरण के सम्बन्ध में विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलकर कुछ तथ्यों का संकलन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है –

अध्ययन के समय समाज के अनेक वर्गो के लोगों से अनेक अपराधों में राजनीतिक संलिप्तता देखने को प्राप्त होती है, इसकी जानकारी निम्न लोगों के माध्यम से एकत्र की गयी है। उन तथ्यों की जानकारी निम्न सारणी से स्पष्ट है–

सारणी 1: अपराधों में राजनीतिक संलिप्तता का अध्ययन

क्र.	वर्ग	अनेक अपराधों में राजनीतिक संलिप्तता देखने को प्राप्त होती है					
		अभिमत		हाँ		नहीं	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	बुद्धिजीवी वर्ग	40	20	24	12	16	8
2	नौकरी पेशा वर्ग	40	20	22	11	18	9
3	व्यापारी वर्ग	40	20	25	12.5	15	7.5
4	जनप्रतिनिधि व समाज के अन्य वर्ग	80	40	42	21	38	19
योग		200	100	113	56.5	87	43.5

उक्त सारणी में अनेक अपराधों में राजनीतिक संलिप्तता देखने को प्राप्त होती है। निदर्शन पद्धति से चयनित समाज के 200 लोगों से प्राप्त किये गये जिनमें से बुद्धिजीवी वर्गों के 20 प्रतिशत, नौकरी पेशा वर्ग के 20 प्रतिशत, व्यापारी वर्ग के 20 प्रतिशत एवं जनप्रतिनिधि व अन्य वर्ग के 40 प्रतिशत लोगों के उत्तर इस प्रकार रहे। बुद्धिजीवी वर्ग के 12 प्रतिशत लोगों द्वारा बताया गया कि अनेक अपराधों में राजनीतिक संलिप्तता देखने को प्राप्त होती है उत्तर हाँ में दिया गया है, एवं 8 प्रतिशत लोगों

द्वारा अनेक अपराधों में राजनीतिक संलिप्तता देखने को प्राप्त होती है इसका उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया। नौकरी पेशा वर्ग के 11 प्रतिशत लोगों द्वारा अनेक अपराधों में राजनीतिक संलिप्तता देखने को प्राप्त होती है इसका उत्तर हाँ में दिया गया है, एवं 9 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं में बताया गया है। व्यापारी वर्ग के 12.5 प्रतिशत लोगों द्वारा बताया गया कि अनेक अपराधों में राजनीतिक संलिप्तता देखने को प्राप्त होती है इसका उत्तर हाँ में दिया गया एवं 7.5 प्रतिशत व्यापारी वर्ग के लोगों द्वारा अनेक अपराधों में राजनीतिक संलिप्तता देखने को प्राप्त होती है का उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार जनप्रतिनिधि एवं अन्य वर्ग के 21 प्रतिशत लोगों द्वारा अनेक अपराधों में राजनीतिक संलिप्तता देखने को प्राप्त होती है का उत्तर हाँ में प्रस्तुत किये हैं एवं 19 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं में दिया गया। इस प्रकार कुल 56.5 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि अनेक अपराधों में राजनीतिक संलिप्तता देखने को प्राप्त होती है एवं 43.5 प्रतिशत लोगों द्वारा अनेक अपराधों में राजनीतिक संलिप्तता देखने को प्राप्त होती है उत्तर नहीं बताया गया।

अध्ययन के समय समाज के अनेक वर्गों के लोगों से पुलिस पर राजनीतिक दबाब को देखकर लोगों के मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि पुलिस अपराधियों से मिली रहती है इसकी जानकारी निम्न लोगों के माध्यम से एकत्र की गयी है। उन तथ्यों की जानकारी निम्न सारणी से स्पष्ट है–

सारणी 2: पुलिस पर राजनीतिक दबाब का अध्ययन

क्र.	वर्ग	पुलिस पर राजनीतिक दबाब को देखकर लोगों के मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि पुलिस अपराधियों से मिली रहती है					
		अभिमत		हाँ		नहीं	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	बुद्धिजीवी वर्ग	40	20	24	12	16	8
2	नौकरी पेशा वर्ग	40	20	22	11	18	9
3	व्यापारी वर्ग	40	20	25	12.5	15	7.5
4	जनप्रतिनिधि व समाज के अन्य वर्ग	80	40	44	22	36	18
योग		200	100	115	57.5	85	42.5

उक्त सारणी में पुलिस पर राजनीतिक दबाब को देखकर लोगों के मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि पुलिस अपराधियों से मिली रहती है। निदर्शन पद्धति से चयनित समाज के 200 लोगों से प्राप्त किये गये जिनमें से बुद्धिजीवी वर्गों के 20 प्रतिशत, नौकरी पेशा वर्ग के 20 प्रतिशत, व्यापारी वर्ग के 20 प्रतिशत एवं जनप्रतिनिधि व अन्य वर्ग के 40 प्रतिशत लोगों के उत्तर इस प्रकार रहे। बुद्धिजीवी वर्ग के 12 प्रतिशत लोगों द्वारा बताया गया कि पुलिस पर राजनीतिक दबाब को देखकर लोगों के मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि पुलिस अपराधियों से मिली रहती है उत्तर हाँ में दिया गया है, एवं 8 प्रतिशत लोगों द्वारा पुलिस पर राजनीतिक दबाब को देखकर लोगों के मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि पुलिस अपराधियों से मिली रहती है इसका उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया। नौकरी पेशा वर्ग के 11 प्रतिशत लोगों द्वारा पुलिस पर राजनीतिक दबाब को देखकर लोगों के मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि पुलिस अपराधियों से मिली रहती है इसका उत्तर हाँ में दिया गया है, एवं 9 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं में बताया गया है। व्यापारी वर्ग के 12.5 प्रतिशत लोगों द्वारा बताया गया कि पुलिस पर राजनीतिक दबाब को देखकर लोगों के मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि पुलिस अपराधियों से मिली रहती है इसका उत्तर हाँ में दिया गया एवं 7.5 प्रतिशत व्यापारी वर्ग के लोगों द्वारा पुलिस पर राजनीतिक दबाब को देखकर लोगों के मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि पुलिस अपराधियों से मिली रहती है का उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार जनप्रतिनिधि एवं अन्य वर्ग के 22 प्रतिशत लोगों द्वारा पुलिस पर राजनीतिक दबाब को देखकर लोगों के मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि पुलिस अपराधियों से मिली रहती है का उत्तर हाँ में प्रस्तुत किये हैं एवं 18 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं में दिया गया। इस प्रकार कुल 57. 5 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि पुलिस पर राजनीतिक दबाब को देखकर लोगों के मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि पुलिस अपराधियों से मिली रहती है एवं 42.5 प्रतिशत लोगों द्वारा पुलिस पर राजनीतिक दबाब को देखकर लोगों के मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि पुलिस अपराधियों से मिली रहती है उत्तर नहीं बताया गया।

अध्ययन के समय समाज के अनेक वर्गों के लोगों से अपराध नियंत्रण में एक मुख्य समस्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होना है इसकी जानकारी निम्न लोगों के माध्यम से एकत्र की गयी है। उन तथ्यों की जानकारी निम्न सारणी से स्पष्ट है–

सारणी 3: अपराध नियंत्रण में एक मुख्य समस्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण का अध्ययन

क्र.	वर्ग	अपराध नियंत्रण में एक मुख्य समस्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होना है					
		अभिमत		हाँ		नहीं	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	बुद्धिजीवी वर्ग	40	20	22	11	18	9
2	नौकरी पेशा वर्ग	40	20	24	12	16	8
3	व्यापारी वर्ग	40	20	28	14	12	6
4	जनप्रतिनिधि व समाज के अन्य वर्ग	80	40	44	22	36	18
योग		200	100	118	59	82	41

उक्त सारणी में अपराध नियंत्रण में एक मुख्य समस्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होना है। निदर्शन पद्धति से चयनित समाज के 200 लोगों से प्राप्त किये गये जिनमें से बुद्धिजीवी वर्गो के 20 प्रतिशत, नौकरी पेशा वर्ग के 20 प्रतिशत, व्यापारी वर्ग के 20 प्रतिशत एवं जनप्रतिनिधि व अन्य वर्ग के 40 प्रतिशत लोगों के उत्तर इस प्रकार रहे। बुद्धिजीवी वर्ग के 11 प्रतिशत लोगों द्वारा बताया गया कि अपराध नियंत्रण में एक मुख्य समस्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होना है उत्तर हाँ में

दिया गया है, एवं 9 प्रतिशत लोगों द्वारा अपराध नियंत्रण में एक मुख्य समस्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होना है इसका उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया। नौकरी पेशा वर्ग के 12 प्रतिशत लोगों द्वारा अपराध नियंत्रण में एक मुख्य समस्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होना है इसका उत्तर हाँ में दिया गया है, एवं 8 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं में बताया गया है। व्यापारी वर्ग के 14 प्रतिशत लोगों द्वारा बताया गया कि अपराध नियंत्रण में एक मुख्य समस्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होना है इसका उत्तर हाँ में दिया गया एवं 6 प्रतिशत व्यापारी वर्ग के लोगों द्वारा अपराध नियंत्रण में एक मुख्य समस्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होना है का उत्तर नहीं में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार जनप्रतिनिधि एवं अन्य वर्ग के 22 प्रतिशत लोगों द्वारा अपराध नियंत्रण में एक मुख्य समस्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होना है का उत्तर हाँ में प्रस्तुत किये हैं एवं 18 प्रतिशत लोगों द्वारा इसका उत्तर नहीं में दिया गया। इस प्रकार कुल 59 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि अपराध नियंत्रण में एक मुख्य समस्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होना है एवं 41 प्रतिशत लोगों द्वारा अपराध नियंत्रण में एक मुख्य समस्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होना है उत्तर नहीं बताया गया।

अपराधियों का राजनीतिक व्यक्तियों से सम्बन्ध

हम सभी इस कटु सत्य से परिचित है कि आज का राजनीतिक, अपराधियों के सहयोग से राजनीति में उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं अर्थात् अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण खुले रूप से प्राप्त है, ऐसी स्थिति में पुलिस ऐसे क्रूर अपराधियों पर हाथ डालने में अपने को असहाय महसूस करती है। [15]

वर्तमान समय में राजनीति अपने काले कारनामों को छिपाने का जरिया बन गयी है ऐसे एक नहीं अनेक दृष्टांत हैं जब भी अपराधियों पर पुलिस का दबाब बढ़ा व न्यायतंत्र का शिकंजा कसा तो वह राजनीति में प्रवेश कर गये जिससे आज हमारी संसद व विधानसभाओं में गुण्डों व हिस्ट्रीशीटरों की संख्या खूब बढ़ गयी है, कई आपराधिक प्रकरणों वाले लोग मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गये हैं तो कुछ केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में स्थान ग्रहण कर चुके हैं। [16]

कम्प्यूटर वेबसाइटों पर आज भी देखने को प्राप्त है कि मोहर लगेगी हाथी पर वर्ना गोली लगेगी छाती पर और शरीर (लाश) मिलेगी घाटी पर आदि शब्दों से स्पष्ट है कि इन दुर्दान्त अपराधियों को कहीं न कहीं से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। बुंदेलखण्ड क्षेत्र में ददुआ का भाई बालसिंह चुनाव लड़ा और ददुआ का लड़का वीर सिंह चित्रकूट जिला का पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के रूप में पहले ही जीत चुका है और ये दोनों एक वरिष्ठ नेता के साथ बुंदेलखण्ड क्षेत्र में एक मंच पर देखे गये हैं। फूलन देवी सांसद रह चुकी है एवं सीमा परिहार भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, इसी तरह मोहर सिंह भी जनपद सदस्य है।

इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि दस्यु सरगना भी कहीं न कहीं से राजनीतिक व्यक्तियों से जुड़े रहते हैं। [17]

पुलिस को जनता का असहयोग

पुलिस के सम्बन्ध में लोगों के मन में एक अजीबोगरीब विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है जिसे दुनिया के अधिकांश देश सुधारने में सफल नहीं हुए। सामान्य अवसरों पर जहां पर पुलिस की उपस्थिति का कोई स्वागत नहीं करता, वहीं दूसरी तरफ जब अच्छे कार्यों की जनता प्रशंसा नहीं करती और जनता पुलिस को संदेह की नजर से देखती है। पुलिस अनुशासनबद्ध होने के कारण उसका प्रतिकार भी नहीं कर पाती। शासन के जितने भी विभाग हैं उसमें सर्वाधिक आलोचना पुलिस की ही की जाती है। इस आलोचना में ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण पुलिस को जनता का सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई होती है। [18]

पुलिस को जन सामान्य से सम्पर्क बढ़ाकर जनता में आपसी तालमेल कर उनसे प्रगाढ़ता करना है, तो इसके लिये पुलिस में आधारभूत परिवर्तन करने होगे। इस दिशा में सर्वप्रथम पुलिस के शीर्ष नेतृत्व को अधिक शक्ति सम्पन्न करते हुए उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना होगा। आज भारतीय पुलिस में जैसा डॉ. माथुर ने कहा है नेतृत्व का संकट है। पुलिस संगठन में उत्तम पुलिस नेतृत्व, दक्ष व्यावसायिक प्रबंधकों की आवश्यकता है जिनके अवैयक्तिक नौकरशाही की मूल्य पद्धति के स्थान पर मानवीय लोकतांत्रिक संगठनात्मक मूल्यों के आधुनिक विचार हों, जोर जबरदस्ती, धमकी तथा दण्ड पर आधारित शक्ति के पुराने रास्तों की जगह सहकारिता, साझेदारी, प्रोत्साहन व अनुरोध पर आधारित अधिकार, शक्ति के नये दृष्टिकोण हों, आज के बदलते हुए परिवेश में नये मूल्यों एवं विचारों को मनोवैज्ञानिक पद्धति से समझने व ग्राहय करने की दक्षता हो।

पुलिस को जनता में सहयोग प्राप्त करने के लिये, पुलिस प्रशासन को एक नये दृष्टिकोण से विचार करना होगा और ऐसी प्रक्रिया अपनानी होगी जिसमें पुलिस को सामाजिक नियंत्रण तथा समाजीकरण के मात्र प्रतिनिधि के रूप में ही नहीं बल्कि योजनाबद्ध प्रगति और परिवर्तन की इस प्रक्रिया में एक सक्रिय अंग के रूप में अपनी भूमिका प्रदर्शित करे। यह तभी संभव हो सकता है जब एक ओर समाज और दूसरी ओर पुलिस प्रशासन मिलकर संयुक्त प्रयास करे, जिससे सामाजिक शक्तियों को संतुलित विकास की गति मिल सके। [19]

निष्कर्ष

अध्ययन के दौरान शोध के निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए है–

- शोध क्षेत्र में 56.5 प्रतिशत समाज के अनेक वर्गों के लोगों से अनेक अपराधों में राजनीतिक संलिप्तता देखने को प्राप्त होती है, जबकि 43.5 प्रतिशत वर्गों का मानना है कि समाज के अनेक वर्गों के लोगों से अनेक अपराधों में राजनीतिक संलिप्तता देखने को प्राप्त नही होती है।
- शोध क्षेत्र में 57.5 प्रतिशत ने समाज के अनेक वर्गों के लोगों से पुलिस पर राजनीतिक दबाब को देखकर लोगों के मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि पुलिस अपराधियों से मिली रहती है, जबकि 42.5 प्रतिशत अपराधियों से नहीं मिली रहती है।
- शोध क्षेत्र में 59.00 प्रतिशत अध्ययन के समय समाज के अनेक वर्गों के लोगों से अपराध नियंत्रण में एक मुख्य समस्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होना बताया है, जबकि 41.00 प्रतिशत अपराध नियंत्रण में एक मुख्य समस्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नही होना है।

सन्दर्भ

1. माथुर डॉ. कृष्णमोहन – स्वातंत्रयोत्तर भारत में जनता का उत्तरदायित्व तथा पुलिस की भूमिका, पृष्ठ 49
2. मिश्र डॉ. शालिकराम – दस्यु उन्मूलन पर पुलिस की भूमिका, पृष्ठ 137
3. मिश्र डॉ. शालिकराम – दस्यु उन्मूलन पर पुलिस की भूमिका, पृष्ठ 117
4. भटनागर सतीशचन्द्र – पुलिस और समाज, पृष्ठ 89, 90
5. श्रीवास्तव डॉ. अम्बरीष कुमार – पुलिस और समाज, पृष्ठ 99
6. मिश्रा डा. शालिकराम – दस्यु उन्मूलन पर पुलिस की भूमिका, पृष्ठ 109, 110
7. मिश्रा डॉ. शालिकराम – दस्यु उन्मूलन पर पुलिस की भूमिका, पृष्ठ 111

8. मिश्रा डॉ. शालिकराम – दस्यु उन्मूलन पर पुलिस की भूमिका, पृष्ठ 112
9. डॉ. एस. अखिलेश – पुलिस और समाज, पृष्ठ 353, 354
10. मिश्रा डॉ. शालिकराम – दस्यु उन्मूलन पर पुलिस की भूमिका, पृष्ठ 112, 113
11. मिश्रा डॉ. शालिकराम – दस्यु उन्मूलन पर पुलिस की भूमिका, पृष्ठ 114, 115
12. श्रीवास्तव डॉ. अम्बरीष कुमार – पुलिस और समाज, पृष्ठ 141, 142
13. मिश्रा डॉ. शालिकराम – दस्यु उन्मूलन पर पुलिस की भूमिका, पृष्ठ 117
14. भटनागर, सतीशचन्द्र पुलिस और समाज, पृष्ठ 126, 127
15. मिश्रा डॉ. शालिकराम – दस्यु उन्मूलन पर पुलिस की भूमिका, पृष्ठ 133
16. मिश्रा डॉ. शालिकराम – दस्यु उन्मूलन पर पुलिस की भूमिका, पृष्ठ 134
17. मिश्रा डॉ. शालिकराम – दस्यु उन्मूलन पर पुलिस की भूमिका, पृष्ठ 133
18. मिश्रा डॉ. शालिकराम – दस्यु उन्मूलन पर पुलिस की भूमिका, पृष्ठ 137
19. डॉ. एस. अखिलेश – पुलिस और समाज, पृष्ठ 313